Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 10, 2013
(BHADRA 19, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 10th September, 2013

No. 28—HLA of 2013/76.—The Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Bill, 2013, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 28—HLA of 2013

THE HARYANA SALARIES AND ALLOWANCES OF MINISTERS (AMENDMENT) BILL, 2013

A

BILL

further to amend the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Haryana Salaries and Allowances of Ministers (Amendment) Act, 2013. Short title.

2. In sub-section (1) of section 3 of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970, for the words "forty thousand rupees", words "fifty thousand rupees" shall be substituted. Amendment of section 3 of Haryana Act 3 of 1970

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As present Ministers and Ministers of State are being paid Salary @Rs. 40,000/- per month as per Section 3(1) of the Haryana Salaries and Allowances of Ministers Act, 1970.

Keeping in view the rise in the cost of living, the Government has decided to increase the Salary of Ministers and Ministers of State from Rs. 40,000/- per month to Rs. 50,000/- per month.

RANDEEP SINGH SURJEWALA,
Parliamentary Affairs Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh :
The 10th September, 2013.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed increase in Salary of Ministers and Ministers of State will entail an extra expenditure of approximately Rs. 13,20,000/- (Rs. thirteen lacs twenty thousand only) per year from the State Exchequer.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2013 का विधेयक संख्या 28—एच०एल०ए०

हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) विधेयक, 2013
हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता (संशोधन) अधिनियम, 2013, कहा जा सकता है।

1970 के हरियाणा अधिनियम 3 की धारा 3 का संशोधन।

2. हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप-धारा (1) में, "चालीस हजार रुपये" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

वर्तमान में हरियाणा मंत्री वेतन और भत्ता अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अनुसार मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को 40,000/- रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा है।

जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतों में बढौतरी के कारण सरकार ने निर्णय लिया है कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का वेतन 40,000/- रुपए से बढ़ा कर 50,000/- रुपए प्रतिमाह कर दिया जाए।

रणदीप सिंह सुरजेवाला,
संसदीय कार्य मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़ सुमित कुमार,
दिनांक 10 सितम्बर, 2013. सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के वेतन में प्रस्तावित बढ़ौतरी के परिणाम स्वरूप राजकोष पर लगभग रूपए 13,20,000/- (तेरह लाख, बीस हजार रुपए) का प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्चा आएगा।

51494—H.V.S.—H.G.P., Chd.